

## वरीयता अनुक्रम

- \* अग्रता-क्रम में इनका सही अनुक्रम है-
  - भारत में मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव
- \* भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है
  - भूतपूर्व राष्ट्रपति
- \* भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है
  - भारत के मंत्रिमंडल सचिव

## संसद (1)

- \* लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है -
    - 25 वर्ष
  - \* 84 वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या, 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है
    - 2026
  - \* भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है
    - 552
  - \* लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी
    - 31वें संशोधन ने
  - \* भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन.....जनगणना के आधार पर है।
    - 1971
  - \* लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है
    - जनसंख्या आधार पर
  - \* इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण नहीं है—
    - अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय
  - \* इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है—
    - केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
  - \* यदि किसी राज्य के लिए लोक सभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी—
- नोट : अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वहीं होगा, जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात

उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोक सभा सदस्यों की संख्या 42 थी जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 हैं।

- \* लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं
  - मध्य प्रदेश में
- \* लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है
  - भारत के राष्ट्रपति के पास
- \* राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है
  - अनुच्छेद 333 के द्वारा
- \* राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
  - 2 सदस्यों को
- \* राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं
  - 7 वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन
- \* लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है
  - प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
- \* लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं
  - वर्ष में दो बार
- \* लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है
  - कुल सदस्य संख्या का 1/10
- \* लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है—
  - 550
- \* लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है
  - 545
- \* संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है
  - संसद के दोनों सदनों में
- \* लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है
  - स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा
- \* लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है— राष्ट्रपति
- \* लोकसभा का कार्यकाल
  - आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
- \* लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है
  - उत्तर प्रदेश
- \* जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है,
  - लोक सभा में प्रथम स्थान-उत्तर प्रदेश - 80 सीटें
  - द्वितीय स्थान-महाराष्ट्र - 48 सीटें
  - तृतीय स्थान- प. बंगाल - 42 सीटें
- \* लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है
  - 25



\* सही सुमेलित हैं—

राज्य	प्रतिनिधित्व
(i) आंध्र प्रदेश	— 25
(ii) तमिलनाडु	— 39
(iii) महाराष्ट्र	— 48
(iv) छत्तीसगढ़	— 11
(v) पश्चिम बंगाल	— 42

नोट-ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक् हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं।

\* लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं — त्रिपुरा से  
\* राज्यों/संघशासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है—

— बंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम

\* डिजिटल डिस्टेंस के बाद यू.पी. में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है — उन्नाव

\* वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है — 70 लाख रु.

\* लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था — 1952 में

\* नवीं लोकसभा भंग की गई — 13 मार्च, 1991 को

\* भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए— फरवरी, 1998 को

\* कथन (A): रा.ज.ग. सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद-विवाद (discussion) पर संघ नहीं करती है।

कारण (R): इस नियम में वाद-विवाद के साथ-साथ मतदान का भी प्रावधान है।

— A तथा R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है

\* लोकसभा का नेता है — प्रधानमंत्री

\* लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) निर्वाचन-क्षेत्र है — तदुल्ल

\* भारत में लोकसभा का (स्पीकर) अध्यक्ष — चयनित किया जाता है

\* लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है—

— लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा

\* लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है — उपाध्यक्ष को

\* लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है

— लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा

\* प्रो-टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है — सदस्यों को शपथ दिलाना

\* लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपने 'कॉस्टिंग वोट' का प्रयोग केवल करते हैं

— जब वोट बराबर-बराबर होने के नाते 'टाय' (Tie) हो

\* संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा — अनुच्छेद 100

\* लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे — जी.वी. मावलंकर

\* प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था— — जी.वी. मावलंकर

\* लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं — श्रीरा कुमार

\* लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं — एम. थाम्मी दुरई

\* यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह

— मत-बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं।

\* प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे — पी.ए. संगमा

\* लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है — लोकसभा अध्यक्ष

\* लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है

— वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं—  
लोकसभा चुनाव - सामान्य वर्ग - 25,000 रु.

अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 12,500 रु.

राज्य विधान सभा - सामान्य वर्ग - 10,000 रु.

अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 5,000 रु.

\* लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है

— द्वितीय वाचन में

\* निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं—

I. धन/वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

II. धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में।

III. मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में।

## संसद (2)

\* राज्य सभा में होते हैं

— 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

\* राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है

— उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर

\* राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं—

— राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

\* राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है — 6 वर्ष का



- \* राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि—  
— इसे विघटित नहीं किया जा सकता है
- \* हमारे संविधान के अनुसार, राज्यसभा का कार्यकाल — समाप्त होने का विषय नहीं है।
- \* प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई — ररगिस दत्त
- \* राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है  
— इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं
- \* राज्यसभा की एकल शक्ति के अंतर्गत आता है  
— नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
- \* राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है—
- (i) राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है।
- (ii) राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा।
- (iii) ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है।
- \* राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिवक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यदि इसके लिए एक संकल्प—
- राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
- \* सही कथन हैं—  
1. राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।  
2. राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
- \* वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं
- संसद को, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना
- \* संसद को राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है — अनुच्छेद 249
- \* भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही-सही वर्णित करता है  
— इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है
- \* सही सुमेलित है—  
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें - 18  
महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें - 19  
कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें - 12  
प. बंगाल में राज्यसभा की सीटें - 16
- (तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं)

- \* राज्यसभा का अध्यक्ष — उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है।
- \* राज्य सभा के वर्तमान सभापति हैं — कैलाश नायडू
- \* राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु उर्हताओं के संदर्भ में सही है—  
(1) उम्र कम-से कम 30 वर्ष होना चाहिए  
(2) राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए
- \* राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है — 250
- \* राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात होगा
- लोकसभा, राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है
- \* राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है — मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो
- \* राज्यसभा के विषय में सही है—  
1. यह भंग नहीं की जा सकती है।  
3. प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

### संसद (3)

- \* कथन (A): अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।  
कारण (R): संसद, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है।  
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है — दो बार
- \* संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए—  
— छः महीने का
- \* भारत के संविधान में कथित है—  
(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा  
(2) संसद राष्ट्रपति और दो सदनों में मिलकर बनेगी
- \* भारतीय संसद बनती है — लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से
- \* संसद का अनन्य भाग नहीं है — उपराष्ट्रपति
- \* संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं—  
1. अध्यक्ष, लोकसभा  
2. उपाध्यक्ष, लोकसभा  
3. महासचिव लोकसभा  
4. अध्यक्ष, राज्यसभा
- \* संसद/विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है — 60 दिन



- \* सर्वप्रथम एक सांसद/विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी साठ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा — **राज्यसभा का**
- \* संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है — **अनुच्छेद 105**
- \* किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, जब वह — **किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है।**
- \* लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है — **राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को**
- \* सही कथन है — **किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय बर्जना नहीं है**
- \* संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है
  1. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु
  2. संबंधित राज्य की सहमति से
  3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में।
  4. राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे।
- \* भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती, जब तक — **राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।**
- \* अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है — **बिना किसी राज्य की सहमति से**
- \* संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है — **संसद**
- \* धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है — **यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे**
- \* सदन का अध्यक्ष, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है- — **बैठ जाना (Yielding the floor)**
- \* 'शून्यकाल' संसदीय व्यवस्था की देन है — **भारत की**
- \* लोकसभा में 'शून्यकाल' की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है — **एक घंटा**
- \* संसद में शून्यकाल का समय है — **दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक**
- \* राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है- — **प्रश्न-उत्तर सत्र**
- \* अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है- — **अनु. 253 के अंतर्गत**
- \* कथन सही है — **धन विधेयक लोकसभा में पुरःस्थापित किया जाता है।**
- \* लोकसभा द्वारा पारित धन-विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती- — **14 दिनों तक**
- \* राज्यसभा को 'धन विधेयक' प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए — **14 दिनों के अंदर**
- \* जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे पारित किया जाना होता है — **उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा**
- \* संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा — **लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)**
- \* संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है- — **एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो**
- \* सही कथन हैं-
  1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संसदीकृत है
  2. लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी
  3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग (निरसन) बिल को पारित करने के लिए हुई थी
- \* भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी- — **दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में**
- \* लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है — **साधारण विधि-निर्माण को पारित करने की स्थिति में**
- \* कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है — **दोनों में से संसद के एक पटल पर**
- \* कथन सही है — **राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।**
- \* सही कथन है — **जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।**



- \* भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
  - भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते
- \* भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है
  - भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशना
- \* भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
  - भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते
- \* भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है
  - भारत की संसद
- \* आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं
  - संसदीय स्वीकृति से पूर्व
- \* करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है
  - भारत की संचित निधि में
- \* संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है
  - अनुच्छेद 110 के अंतर्गत
- \* कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं इसका निर्णय करता है
  - लोकसभा अध्यक्ष
- \* धन विधेयक के बारे में सही है—
  - लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
- \* सही कथन है
  - धन-संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, राज्यसभा किसी धन-विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है
- \* वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है
  - कर से संबंधित उपबंध, उधार (ऋण) लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध
- \* कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्भूत है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे—
  - संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
- \* बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है—
  - बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है
- \* भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियाँ हैं—
  1. संसद के सामूहिक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
  2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना
  3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
  4. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना
- \* संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है
  - आर्थिक कार्य विभाग
- \* यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, तो
  - प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र पेश कर देता है
- \* व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई
  - व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के
- \* आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है
  - आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व
- \* 'लेखानुदान' संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है
  - निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए
- \* संसद में 'लेखा के लिए वोट' आवश्यक होता है
  - जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती।
- \* लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है
  - लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं।
- \* व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है
  - अनुदान के अनुरोध के रूप में
- \* भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है
  - लोकसभा में
- \* सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं—
  1. बजट का प्रस्तुतीकरण
  2. बजट पर चर्चा
  3. विनियोग विधेयक को पारित करना
  4. वित्त विधेयक को पारित करना
- \* संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है
  - (1) एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर
  - (2) ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो
  - (3) राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर
  - (4) धन विधेयक पर
- \* संदर्भित संबंध संघीय बजट से है
  - कटौती प्रस्ताव
- \* पार्लियामेंट द्वारा, 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है
  - 18 वर्ष



- \* रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है — संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा
- \* भारतीय राजनीति के संदर्भ में, कथन सही है — राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं
- \* संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है — प्राक्कलन समिति
- \* प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है — एक वर्ष का
- \* सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है — भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
- \* संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है — क्रमशः दो और एक के अनुपात में
- \* ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है — स्थगन प्रस्ताव को
- \* तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है (i) उत्तर मौखिक दिए जाते हैं (ii) पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं
- \* भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है — सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु।
- \* संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है — हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
- \* भारतीय संसद का सचिवालय — सरकार से स्वतंत्र है
- \* भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है — न्यायिक समीक्षा से
- \* भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था — 13-5-2002 को
- \* वह कौन राष्ट्रवादी नेता था, जो 1925 में केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया — बिठ्ठल भाई पटेल
- \* सही कथन है— — लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- \* सही कथन है— (1) लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं (2) संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है (3) विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों परिषदों मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है।
- \* राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है — प्राक्कलन समिति में
- \* सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है — संसद को
- \* लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है — लोकसभा के स्पीकर को
- \* संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है — शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्यूट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण
- \* लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं — 22 (15 लोक सभा तथा 7 राज्य सभा के)
- \* लोक लेखा की संसदीय समिति 1. सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है 2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है सही सुमेलन इस प्रकार है
- लोक लेखा समिति वित्तीय समिति
- बाधिका समिति कार्यकारी समिति
- स्टॉक बाजार-स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति
- विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति
- \* राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है — इस्टीमेट्स कमेटी से
- \* प्राक्कलन समिति गठित की जाती है — लोकसभा के सदस्यों से
- \* भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं 1. सार्वजनिक लेखा समिति, 2. प्राक्कलन समिति, 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति
- \* संसदीय समिति गठित की गई हैं — सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आंकड़ों के बारे में
- \* 2-जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे — 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से
- \* 2-जी स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे — पी.सी. चाको
- \* भारतीय संसद प्रशासन (Administration) पर नियंत्रण करती है — संसदीय समितियों के माध्यम से

## संसद (4)

- \* 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम' प्रथम बार लागू हुआ था — 1954 में
- \* सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं — संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय
- \* सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा



- \* सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है  
— संपूर्ण भारत पर
- \* सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है  
— निदेशक, प्रबंधक, सचिव
- \* घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है  
— 26 अक्टूबर, 2006 को
- \* सामाजिक अधिनियम है  
— एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रीवेन्शन ऑफ इमॉरल ट्रेफिक एक्ट
- \* भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन सही है  
— (i) उपभोक्ताओं को खर्च की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। (ii) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- \* त्रिनिटल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था — 1871 में
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है  
— 30 जनवरी, 1990 को
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं  
— केंद्र सरकार को
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है  
— एक वर्ष
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार \_\_\_\_\_ की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।  
— उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो आधारित है  
— संरक्षा विधेयक का सिद्धांत पर
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और बसूल करने की शक्ति है  
— राज्य सरकार को
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय उपधारित कर सकता है  
— दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है  
— धारा 6 में
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है  
— गिरफ्तारी पूर्व जमानत
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है  
— धारा 18 में
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो \_\_\_\_\_ रैंक से कम न हो।  
— उप-अधीक्षक
- \* वे शक्तियां जिन्हें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई है  
— (i) किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का सम्पहरण (ii) ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना (iii) ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है।
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता  
— सामूहिक जुर्माना आरोपित करना
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है  
— शीघ्र विचारण
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति' के गठन का उपबंध किया गया है  
— धारा 17 के अंतर्गत
- \* सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है  
— (i) स्वशासन प्रदान करना (ii) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना (iii) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
- \* संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई  
— 15 जून, 2005 को
- \* सूचना का अधिकार के संबंध में सही है  
— यह एक विधिक अधिकार है
- \* सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष  
— 2005 में
- \* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है  
— नमिता शर्मा बनाम भारत संघ



- \* **कथन (A) :** सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनुष्यवाद बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है।
- कथन (R) :** इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है
  - सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच
- \* इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर.टी.आई. आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने
- \* अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा
  - ग्राम सभा
- \* राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के आनुसंग्य अधिनियमित हुए थे
  - स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के आनुसंग्य, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है।
- \* भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में कथन सत्य है
  - इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था

## सर्वोच्च न्यायालय

- \* भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था
  - 28 जनवरी, 1950 को
- \* भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है
  - 31
- \* भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
  - भारतीय संविधान के द्वारा
- \* सही कथन है—
  - (i) सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। (ii) सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
- \* भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है
  - संसद में
- \* सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर
  - राष्ट्रपति को

- \* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.....के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
  - संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने
- \* सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है
  - 65 वर्ष
- \* उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है
  - संसद द्वारा
- \* भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान हैं
  - (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है। (ii) न्यायाधीशों का वेतन भारत की संविधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है।
- \* सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं
  - किसी भी न्यायालय में नहीं
- \* भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है
  - राष्ट्रपति
- \* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा
  - सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ
- \* सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (Adhoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जब
  - न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता
- \* भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है
  - सर्वोच्च न्यायालय में
- \* सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश, जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या होती है
  - 4
- \* उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए
  - पांच
- \* केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है—
  - मूल अधिकारिता के अंतर्गत
- \* उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं
  - भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
- \* उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी—
  - गोलकनथ केस में
- \* उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढाँचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था
  - केशवानंद भारती वाद में



- \* उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि "मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।"
- गोलकनथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में
- \* सही सुनेलित है—  
इंदिरा साहनी वाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत  
विशाखा वाद - अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण  
मेनका गांधी वाद - अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं हैं।
- \* संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है — अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनु. 132 को पढ़ना
- \* संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके—  
— अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
- \* सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है  
— यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है।
- \* भारत में सुधारालोक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है— — अनुच्छेद 142 के अंतर्गत
- \* उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अविवृत करता है — अनुच्छेद 137
- \* न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय  
— राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है
- \* न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है  
— भारत और यू.एस.ए. दोनों में
- \* न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है — अनुच्छेद 122 के अंतर्गत
- \* कोई भी संविधान (संशोधन) कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह  
— विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है।
- \* भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है  
— विधि का शासन
- \* संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है  
— सर्वोच्च न्यायालय को
- \* भारत के संविधान का अभिरक्षक (Custodian) है  
— भारत का उच्चतम न्यायालय
- \* उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है  
— राष्ट्रपति को
- \* उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है — खंड (1), अनुच्छेद 143 के अंतर्गत
- \* विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है — संसद को
- \* भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है  
— संसद द्वारा विधि बनाकर
- \* उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही हैं  
— परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर बंध किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
- \* भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है — तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का 'अनुलंघनीय मौलिक ढांचा' घोषित किए गए हैं  
— अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227
- \* भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है — 32 अनुच्छेद के तहत
- \* सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम-से-कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए — 10 वर्ष
- \* "मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा... भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा.....अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा....संविधान और कानून की रक्षा करूंगा।" यह शपथ ली जाती है  
— भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- \* उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं  
— मूल अधिकारों का प्रवर्तन
- \* देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है  
— सर्वोच्च न्यायालय के पास
- \* हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है — अनुच्छेद 355 को
- \* सही कथन है  
— न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका (PIL) के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं।
- \* भारत में 'संविधान की मूल संरचना (बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत' का स्रोत है  
— न्यायिक व्याख्या



- \* भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय" है। इसका आशय है कि
  - इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
- \* अभिलेख न्यायालय माना जाता है
  - उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को
- \* भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है
  - सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
- \* उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है
  - राष्ट्रपति के अनुमोदन से
- \* टी.डी.एस.ए.टी. के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है
  - केवल सुप्रीम कोर्ट में
- \* जनहित याचिका की शुरुआत की गई
  - न्यायिक पहल द्वारा
- \* पी.आई.एल. है—
  - पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन
- \* जनहित याचिका (पी.आई.एल.) प्रस्तुत की जा सकती है
  - उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में
- \* लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्गम देश है
  - यू.एस.ए.
- \* भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है
  - जनहित याचिका से
- \* सितंबर, 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वह न्यायालय है—
  - भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- \* यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा
- \* उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक 'पिंसबंद तोता' है
  - कोयला आवंटन घोटाला वाद में

## राज्यपाल

- \* संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्राक्घानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि—
  - इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था।

- \* राज्य का राज्यपाल मंत्रिमंडल के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है—
  1. विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
  2. मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।
  3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए।
  4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
- \* राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है
  - अनुच्छेद 200 के अधीन
- \* राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष/संवैधानिक प्रमुख है
  - राज्यपाल
- \* जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है
  - भारत का राष्ट्रपति
- \* भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही हैं—
  - उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
- \* राज्यपाल के संबंध में सही कथन हैं—
  - राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है।
- \* राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है
  - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- \* किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य है—
  - (a) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है
  - (b) वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है
  - (c) सामान्यतया वह पांच वर्ष तक पद पर रहता है
- \* सही कथन है
  - भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है
- \* जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे
  - इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अर्द्धांशित करें।
- \* किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं
  - भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।



- \* किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी आर्डिनैस का अनुमोदन होना आवश्यक है — राज्य की विधायिका द्वारा
  - \* राज्यपाल की नियुक्ति करता है — भारत का राष्ट्रपति
  - \* किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद — 155 के तहत होती है
  - \* राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है
    - (i) वह राज्य की विधायिका का अंग होता है।
    - (ii) वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है।
    - (iii) उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं।
  - \* कथन (A): "राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"
 

कारण (R): "राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है।"

— (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
  - \* राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं — कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से
  - \* राज्यपाल उत्तरदायी होता है — राष्ट्रपति के प्रति
  - \* भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है — राज्यपाल
  - \* भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है — राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध
  - \* स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनीं— — सरोजिनी नायडू (उ.प्र.)
  - \* पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थीं — पद्मजा नायडू
  - \* प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, — सरोजिनी नायडू की स्मृति में
  - \* राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था — रघुकुल तिलक थे
- ## राज्य विधानमंडल
- \* मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है-
    - (i) वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है।
    - (ii) वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
    - (iii) उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।
  - \* भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है-
    - राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है
  - \* भारत में राज्य विधानपालिकाओं (State Legislatures) का उच्च सदन है — विधानपरिषद
  - \* विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है — 4 माह तक
  - \* राज्य में धन विधेयक (मनी बिल) प्रस्तुत किया जा सकता है — केवल विधानसभा में
  - \* राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर — राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
  - \* राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है — अनुच्छेद 171 के अंतर्गत
  - \* राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है
    - संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा
  - \* किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के— — अनुच्छेद 169 में
  - \* भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है — अनुच्छेद 169 में
  - राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा
  - \* उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है — कुल सदस्यों का 1/6
  - \* इनको भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है — राज्य विधान परिषदों को
  - \* यहां अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 में उसके लिए उपबंध है — मध्य प्रदेश
  - \* राज्य विधान परिषद के विषय में सही है—
    - (i) यह एक स्थायी सदन है।
    - (ii) वह भंग नहीं किया जा सकता।
    - (iii) प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
    - (iv) इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
  - \* भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है — अनुच्छेद 170
  - \* अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में साठ से कम सदस्य नहीं होंगे — सिक्किम
  - \* भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं — 500
  - \* राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है — भारत का निर्वाचन आयोग
  - \* विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है — उत्तर प्रदेश में



- \* राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरहता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है — राज्यपाल
- \* विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है — 25 वर्ष
- \* यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) पद त्यागना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए — उपाध्यक्ष को
- \* विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर बना रहता है — विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक।
- \* बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है — छः माह तक
- \* राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है — राज्य विधानसभा द्वारा
- \* राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है — राज्यपाल द्वारा
- \* सही कथन है — कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा, यदि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो।
- \* भारत में एकमात्र राज्य है, जहां “सामान्य (कॉमन) सिविल कोड” लागू है — गोवा
- \* वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं — 5
- \* किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है — (i) मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। (ii) सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। (iii) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।
- \* मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं— (i) मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। (ii) मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। (iii) मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष रखता है।
- \* मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है — अनुच्छेद 167
- \* जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य-अवधि होती है — छह वर्ष
- \* भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थीं — उत्तर प्रदेश में
- \* भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी — सुचेता कृपलानी

- \* जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में ‘सदर-ए-रियासत’ से ‘राज्यपाल’ में बदल दिया गया — जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठें संशोधन द्वारा
- \* राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है

I. भारत के राष्ट्रपति के

II. राज्यसभा के सदस्यों के

III. राज्य विधान परिषद के सदस्यों के

- \* ‘राज्य की आकस्मिक निधि’ की स्थापना के लिए उत्तरदायी है — किसी राज्य का विधानमंडल
- \* सही कथन है — किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

## उच्च न्यायालय

- \* उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं — राज्य की समेकित निधि से
- \* उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है — 62
- \* सही कथन है— (i) पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है।
- \* भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है— — चौबीस
- \* जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है— — उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के
- \* उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं — सैद्धान्तिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार
- \* यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है — इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- \* अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है — कलकत्ता
- \* एक से अधिक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए है — बंबई उच्च न्यायालय
- \* मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं — मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर



- \* उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं (संघ राज्य-क्षेत्र शामिल नहीं हैं)

**नोट — संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं—**

- (1) गुवाहाटी उच्च न्यायालय - अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मिजोरम। (2) बंबई उच्च न्यायालय - महाराष्ट्र और गोवा। (3) पंजाब एवं हरियाणा - पंजाब और हरियाणा।  
(4) तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना।

- \* उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक "बेंच" हैं

**नोट —** कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और दो बेंच ग्वालियर और इंदौर हैं, मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ बंबई और तीन बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और तीन बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थीं, परंतु मार्च, 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात् अब तीन बेंच शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 बेंचें हैं।

- \* उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं

— मूल अधिकारों का संरक्षण

- \* एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह, ऐसा कार्य करे, जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट (याचिका) को कहा जाता है

— मंडमस

- \* जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं—

— परमादेश

- \* राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है

— परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

- \* रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है

— प्रतिषेध (प्रोहिबिशन)

- \* एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है

— एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण (रिव्यू) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।

- \* एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है

— उत्प्रेषण

- \* कथन (A) : न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, न्यायालय की अवमानना की कोर्ट में आता है।  
कारण (R) : न्यायिक सक्रियता वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

— A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

- \* कथन (A) : जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है।

कारण (R) : जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है।

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R),

(A) का सही स्पष्टीकरण है।

- \* कथन (A) : भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है।

कारण (R) : भारतीय संविधान "उधार वस्तुओं से भरा बैला है"। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

- \* कथन (A) : भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है।

कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है।

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

- \* बाबरी मस्जिद/सम जनभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ न्यायपीठ) के समक्ष है, का प्रकार है -

— स्वत्वाधिकार मुकदमा (Title suit)

- \* सही कथन है—

— भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है।

- \* एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है

— राष्ट्रपति को

- \* 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया

— न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ

- \* भारत में चलित न्यायालय (Mobile Court) इसका मानसपुत्र है—

— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

- \* प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है

— तीन माह तक

- \* 'विधि आयोग' के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि "प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिये"

— न्यायाधीश एच.आर. खन्ना

- \* 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में सही है

— वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है।



## केंद्र-राज्य संबंध

\* भारत में केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होते हैं—

1. संविधान के प्रावधानों से
2. नियोजन प्रक्रिया से
3. राजनीतिक हिंसा के अंतर्विरोध से
4. हुकूम चलाने की इच्छा प्रबलता से

\* केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है  
— अनुच्छेद 268-281 के अंतर्गत

\* भारत में केंद्र-राज्य संबंध निर्भर करते हैं

1. संवैधानिक प्रावधानों पर
2. परंपराओं तथा व्यवहारों पर
3. न्यायिक व्याख्याओं पर
4. वास्तविक के लिए संवैधानिक पर

\* एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं—

1. संघ और राज्यों के बीच संबंध
2. राज्यों के मध्य संबंध
3. समन्वय के लिए तंत्र
4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र

\* केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं  
— अनुच्छेद 245 तथा 246

\* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है

— राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से

\* अनुच्छेद-249 के खंड (1) के अंतर्गत प्राप्ति प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा  
— एक वर्ष से अधिक समय के लिए

\* वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, उल्लिखित हैं  
— समवर्ती सूची में

\* केंद्र-राज्य संबंध उल्लिखित हैं  
— 7वीं अनुसूची में

\* विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है  
— सातवीं

\* केंद्र-राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं  
— भाग XI में

\* भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं  
— संसद में

\* भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को  
— संघीय सरकार को दिया है

\* केंद्र-राज्य संबंधों को विशेष रूप से 'म्युनिसिपल संबंध' कहा गया है  
— वितीय मामलों में राज्य पर केंद्र के निर्वंत्रण के प्रसंग में

\* संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है  
— अनुच्छेद 355 में

\* भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधित्तर संस्था/संस्थाएं हैं

— राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन

\* झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ

— 8 अगस्त, 1995 को

\* भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है

— अनुच्छेद 263 के अनुसार

\* अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है

— संवैधानिक

\* सही सुमेलित है—

अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनियम की

शक्ति - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956

राष्ट्रीय जल नीति, 1987

\* क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है

— संसदीय कानून द्वारा

\* कथन (A): केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं।

कारण (R): राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

— (A) और (R) दोनों अपनी जगह सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

\* विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है— अनुच्छेद 265 में कहा गया है

\* सरकारी आयोग गठित हुआ था, समीक्षा करने के लिए

— संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की

\* सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है

— केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से

\* अभिकथन (A): सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए।

कारण (R): जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

\* स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद, जो 'अंतर-सरकारी परिषद्' के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया

— सरकारी आयोग ने

\* भारत में संघ-राज्य संबंध से संबंधित है

— सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग

\* संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं

— नहीं

\* राज्य सरकारों को कृषि आय कर समनुदेशित करता है

— भारत का संविधान

\* एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है

— कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर



## आपात उपबंध

- \* भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? — अनुच्छेद 355 के अंतर्गत
- \* भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है — युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
- \* आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है — आंतरिक अशांति
- \* भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा की जा सकती है — अनुच्छेद 352 के अनुसार
- \* इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है—  
— बाह्य आक्रमण, राज्यों में सैद्धान्तिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट
- \* भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं (अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त)  
— अनुच्छेद 359 के अंतर्गत
- \* भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है  
नोट : अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जबकि अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वां संविधान संशोधन) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहां उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
- \* प्रायः राज्यों में 'राष्ट्रपति शासन' लागू किया जाता है — गवर्नर के सहाय पर
- \* इस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान है  
नोट : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में सैद्धान्तिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 370) को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (1964 से) के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में सैद्धान्तिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है।
- \* संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन सही हैं—  
(i) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है।  
(ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।  
(iii) इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए।

- \* संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है — 1 माह अंतराल में
- \* "राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ घोखा है" कहा था — के.एम. नम्बियार ने
- \* भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है — वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है — अनुच्छेद 360 का
- \* भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है — कभी नहीं
- \* भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है — तीन प्रकार के
- \* राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि — आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है।
- \* राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है — 3 वर्ष तक
- \* आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है — संसद द्वारा

## वित्त आयोग

- \* सामान्य रूप में भारत में प्रति पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है — केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
- \* संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है — वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
- \* भारत में, शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर 1. संघ द्वारा लगाए जाते हैं  
2. राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
- \* वित्त आयोग का मुख्य कार्य है — केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
- \* वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति मेजने में मुख्य रूप से संबंधित है: — राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से
- \* भारत में वित्त आयोग का कार्य है — आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहाय्यार्थ अनुदान निर्धारण



- \* कथन (A): राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।  
कारण (R): संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता।— (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- \* संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को — राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
- \* 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — सी. रंगराजन
- \* 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — विजय केलकर
- \* 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे — वाई.वी. रेड्डी
- \* वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा — भारत का राष्ट्रपति
- \* वित्त आयोग का गठन किया जाता है, प्रत्येक — पांचवें वर्ष
- \* राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है — यह एक संवैधानिक संस्था है
- \* संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं—

नोट : अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 14 वें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2014 को सौंपी।

- \* वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और — चार अन्य सदस्य

## योजना आयोग

- \* योजना आयोग का अंत किया — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
- \* योजना आयोग की स्थापना हुई थी — 15 मार्च, 1950
- \* योजना आयोग की स्थापना की गई — संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर
- \* संविधानोत्तर संस्था है — नीति आयोग
- \* वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था — एम.वी. माथुर ने
- \* संवैधानिक निकाय नहीं है — योजना आयोग
- \* इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है
- 1. राष्ट्रीय विकास परिषद
- 2. योजना आयोग
- 3. क्षेत्रीय परिषदें
- \* भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे — पंडित जवाहरलाल नेहरू
- \* योजना आयोग के 'पदेन' अध्यक्ष हैं — प्रधानमंत्री
- \* नीति आयोग के विषय में सही है — (i) इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है।  
(ii) इसका गठन जनवरी, 2015 में किया गया था।  
(iii) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।

- \* योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्त्व का दर्जा दिया गया है — भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
- \* कथन (A) : "योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है", केवल संघ हेतु नहीं, अपितु राज्यों हेतु भी।  
कारण (R) : यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। — (A) एवं (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का।
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद—  
1. राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है।  
2. राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है।  
3. राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करती है।
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं — प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिगण, राज्यों के मुख्यमंत्री
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है — पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है — भारत का प्रधानमंत्री
- \* भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी — 6 अगस्त, 1952 को

## लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

- \* भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था — प्रशासनिक सुधार आयोग ने
- \* राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी — भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)
- \* ओमबुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है — लोकपाल
- \* संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था — 1968 में
- \* उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने
- \* सर्वप्रथम लोकयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी — महाराष्ट्र में
- \* \* उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है — राज्यपाल को
- \* 2011 में लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है — उत्तराखंड
- \* वोहरा समिति.....के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। — राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ



- \* वह समिति, जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी — **बोहरा समिति**
- \* भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी — **राजमन्नार आयोग ने**
- \* 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था — **अनुच्छेद 123**
- \* मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य था — **मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन**
- \* राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं — **लोक सभा का अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष का नेता तथा राज्य सभा में विपक्ष का नेता**
- \* भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है—  
— इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं, आयोग के एक सदस्य के रूप एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है।
- \* मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में 'लोक सेवक' की परिभाषा दी गई है — **धारा 2(M) के अंतर्गत**
- \* कथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।  
कारण (R): उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयुपर्यंत पर (जो भी पहले हो) धारित करता है।  
— **(A) तथा (R) दोनों सही हैं।**
- \* राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- \* राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है — **मानव अधिकारों का उत्त्थान करने वालों को सजा देना।**
- \* संवैधानिक संस्था नहीं है — **मानवाधिकार आयोग**
- \* संवैधानिक प्राधिकरण हैं—  
**1. राज्य निर्वाचन आयोग, 2. राज्य वित्त आयोग, 3. जिला पंचायत**
- \* संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही हैं—  
— इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होगी, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम. एन. वैकटचेतैया कर रहे हैं
- \* संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी, 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं — **एम.एन. वैकटचेतैया**
- \* केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है — **5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक**
- \* स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया, वह था — **मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता**
- \* मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले थे — **मोरारजी देसाई**

- \* मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई — **1980 में**
- \* वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है — **धार्मिक कारण**
- \* राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- \* दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है — **भारत के राष्ट्रपति के द्वारा**
- \* राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है — **सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर**
- \* किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है — **भारत के राष्ट्रपति अनुमोदन से**
- \* लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है — **अनुच्छेद 317 के अंतर्गत**
- \* भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है — **इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना-देना नहीं है**
- \* संघ लोक सेवा आयोग एक — **संवैधानिक संगठन है**
- \* संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है — **राष्ट्रपति को**
- \* यूनिफ़ॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है — **रोज वैथ्यू**
- \* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं — **राज्य की संचित निधि पर**
- \* भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वह था — **गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919**

## अस्थायी विशेष प्रावधान

- \* भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है — **अनुच्छेद 371 में**
- \* भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है— **जम्मू-कश्मीर**
- \* भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ख में विशेष उपबंध प्रावधानित हैं — **असम के लिए**
- \* संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है — **महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए**
- \* भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है — **कश्मीर का अलग संविधान है**
- \* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है — **एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध**



\* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है

— जम्मू-कश्मीर राज्य से

\* भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू-कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं, वे हैं -

— अनुच्छेद 1 एवं 370

\* जम्मू एवं कश्मीर का 'सदर-ए-रियासत' पदनाम बदल कर 'राज्यपाल' कर दिया गया

नोट : जम्मू एवं कश्मीर संविधान में छठें संविधान संशोधन अधिनियम, 1965 द्वारा सदर-ए-रियासत नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर-ए-आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया।

## चुनाव आयोग

\* मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन हैं—

— (i) मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है, जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।

(ii) मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।

\* भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है

— सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष

\* भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है

— 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो

\* मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है

— संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर

\* निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है

— मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा

\* भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है

— राष्ट्रपति द्वारा

\* भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है

— अनुच्छेद 324 के अंतर्गत

\* भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं—

I. संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना।

II. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना।

III. निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं निबंधन।

\* राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है

— भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा

\* भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं

1. वयस्क मतधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली।

2. एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुषांगिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली।

\* भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है

— निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना

\* संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेंगे। — भारत के निर्वाचन आयोग की

\* यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि (जमानत राशि) खो देता है, तो उसका अर्थ है कि

— निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी

\* न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है — संसद द्वारा

\* भारत में मतधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है

— विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)

\* नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया, इस आम चुनाव में

— 1989 के

\* केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई

— 61 वें संशोधन (1989) द्वारा

\* 'निर्गम मत सर्वेक्षण' के विषय में कथन सही है

— निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है,

जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मतधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया।

\* जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही हैं

— (i) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी।

(ii) लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अम्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है।

(iii) चुनाव लड़ने वाले किसी अम्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता।

\* दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी

— लोकसभा के चुनाव के सरकारी निर्वाचन की।



\* दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था

— निर्वाचन सुधारों से

\* उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, जहां

— द्वि-दलीय प्रणाली विकसित हुई है

\* कथन (A) : संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात् निर्वाचन आयोग को दी गई हैं।

कारण (R) : निर्वाचन आयोगों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है।

— A और R दोनों सही हैं, किंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है A का

\* निर्वाचन आयोग को 'तीन सदस्यीय आयोग' बनाया गया

— 1989 से

\* इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता

— स्थानीय निकायों का

\* परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है—

1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

\* राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है — 25 जनवरी को

\* कथन (A) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है।

कारण (R) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हिंदू और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है।

— (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R) सही व्याख्या है (A) की

\* आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रियाप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है — अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को

\* कथन (A) : राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है।

कारण (R) : ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। — (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

## राजनीतिक दल

\* भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है, यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम—

— चार राज्यों में

\* किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि — वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा

चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है।

\* किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, जब वह—

(i) उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत और साथ ही कम से कम चार लोकसभा सीटें प्राप्त हों।

(ii) उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम

3 राज्यों से चुने गए हों।

(iii) वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो।

\* 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' में 'राष्ट्रीय' शब्द प्रभावित था

— ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से

\* 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ

— कांग्रेस पार्टी के

\* राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है :

1. यह बयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

2. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी।

3. धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा।

4. राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।

\* भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे

— ए.बी.वाजपेयी

\* 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' का संस्थापक थे — बी.आर. अम्बेडकर

\* डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी — ऑल इंडिया सिक्क्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी

\* सही सुमेलन इस प्रकार है—

(राजनैतिक दल)	(गठन वर्ष)
सी.पी.आई.	1920
सी.पी.एम.	1964
ए.आई.ए.डी.एम.के.	1972
वेलगूदेशम	1982

\* भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सी.पी.आई. और सी.पी.आई.एम. में हुआ था — 1964 में

\* कथन (A) : भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ बायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं।

कारण (R) : वह बहुत से चीजों की वृहद विस्तार में चर्चा करता है।

— दोनों A और R सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।



\* कथन (A) : भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले।

कारण (R) : बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है।

— A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

\* कथन (A) : संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए तैतीस प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

कारण (R) : चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दल, बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके तैतीस प्रतिशत को, महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं।

— A गलत है, परंतु R सही है।

\* भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है — चुनाव आयोग को

\* भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं—

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है।

3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है, जिसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।

\* कथन (A) : भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है।

कारण (R) : अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं।

— A तथा R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

\* आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है

— दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय-समय पर होता है।

\* दल-बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, वह थी

— 15 फरवरी, 1985

\* राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष

— 1985 में

\* दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था

— जम्मू एवं कश्मीर राज्य में

\* लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए

नोट : लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात् 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए।

\* साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से 'भू-पोर्टम' आंदोलन चलाया था

— आंध्र प्रदेश में

\* 'कामराज योजना' का उद्देश्य था

— भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना

\* कथन (A) : भारत में लिखित संविधान है।

कारण (R) : शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आक्रांताओं का संकेतक है।

— (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

## संविधान संशोधन

\* कथन सही है

— मिनर्वा मिल्स बाद, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।

\* संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति "सहमति देनी होगी" शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है — चौबलिसवां संशोधन

\* भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है — संविधान संशोधन विधेयक

\* भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है

— अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत

\* भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है

— या तो लोकसभा में या राज्यसभा में

\* भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समुष्टि आवश्यक है—

1. संविधान के संघीय प्रावधान

2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार

3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया

\* वे विषय, जिन पर कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है — (1) राष्ट्रपति का निर्वाचन

(2) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

(3) सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची

\* भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन (Amendment Act) विधेयक लाया गया — 1951

\* उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब

— विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।